

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI
(PARLIAMENT CELL)**

**Room No.31, Punarvas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002**

No. DD/PC/DUSIB/D- 194

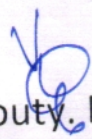
dated: 29/07/21

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Starred question no. 29 dated
30/07/2021.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Starred
question no. 29 raised by Sh. Prakash Jarwal, Hon'ble MLA, duly
approved by the Competent Authority.


Deputy Director(PC)
Phone No. 23370455

Copy to:-

Director(DIP) along with **150 copies**.

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
संसद कक्ष

पुनर्वास भवन, कमरा न0-31
आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या:- 29

दिनांक:- 30-07-2021

प्रश्नकर्ता का नाम:- श्री प्रकाश जारवाल, विधायक

क्र०	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि ब्लॉक 13 दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में प्लॉट नंबर 18 से 25 को अवैध रूप से एक ही प्लॉट में बदल दिया गया है,	हां, प्लॉट नंबर 18 से 25 को एक ही प्लॉट में तब्दील कर दिया गया है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि इन प्लॉटों पर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है.	हां, इन भूखंडों पर एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया गया है।
ग	क्या यह सत्य है कि डीयूएसआईबी ने इन प्लॉटों का एक सर्वे किया था जिसमें इनके मूल आवंटि नहीं पाए गए थे,	यह सत्य है। DUSIB की सर्वे शाखा द्वारा इन प्लॉटों का सर्वे किया गया था।
घ	इन अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इसे गिरान सहित अन्य कोई कार्रवाई न किए जाने क्या कारण है.	प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए, DUSIB Act, 2010 की धारा-41 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हैं।
ङ	सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है; और	कृपया (घ) का उत्तर देखें।
च	इन अवैध गतिविधियों को होने देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?	DUSIB के अंतर्गत आने वाले कार्य के लिए उपरोक्त (घ) में वर्णित अनुसार कार्यवाही की जा रही है। सहायक आयुक्त, सदन एवं समिति दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सम्पत्ति पर अवैध निर्माण के विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट-1957 की धारा 343/344/345- ए के तहत कार्यवाही की गई है एवं दिनांक 11/11/2020 को तोड़फोड़ एवं सीलिंग की कार्यवाही भी की गई है। (कॉपी संलग्न)।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (संसद प्रकोष्ठ)



SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
CORPORATION AND COMMITTEE DEPARTMENT
2nd FLOOR, DR. S.P.M. CIVIC CENTRE
MINTO ROAD, NEW DELHI.

No. F.33/497/VSQ/Starred-29/SDMC/ 351/C&C

Dated: 29.07.2021

To

The Deputy Director, (Parliament Cell),
DUSIB,
Govt. of NCT of Delhi,
Punarwas Bhawan, Room No.31-A,
I.P.Estate, New Delhi.

Sub: Vidhan Sabha Starred Question No.29 by Sh. Prakash Jarwal for 30.07.2021.

I directed to refer to your letter No.एफ.48/ता0प्र0-29/दूसरा सत्र दूसरा भाग-2021/दिविस/श.वि./डी-184 दिनांक 28.07.2021 and say that though the question was required to be forwarded to South Delhi Municipal Corporation by Dy. Secretary (Parliament Cell), UD Department, GNCTD. However, keeping in view the urgency in the matter, the part reply pertaining to SDMC is enclosed herewith.

Encl: As above.


Assistant Commissioner (C&C)
South DMC

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
सदन एवं समिति विभाग
द्वितीय तल, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002.

क: एफ.33/497/तारा/प्रश्न-29/350/स.ए.व.स

दिनांक : 29.07.2021

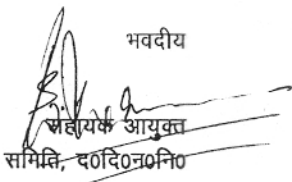
उप-निदेशक (संसद प्रकोष्ठ),
संसद कक्ष,
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
पुनर्वास भवन, कमरा न0 -31,
आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली.

विषय: विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 29 माननीय विधायक श्री प्रकाश जारवाल, दिनांक 30.07.2021 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एफ.48/ता0प्र0-29/दूसरा सत्र दूसरा भाग-2020/दिविस/श.वि./डी-184 दिनांक 28.07.2021 के सन्दर्भ में श्री प्रकाश जारवाल, विधायक द्वारा उठाए गये मामले के सदर्थ में विभागीय उत्तर निम्नलिखित है:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि ब्लॉक 13, दक्षिणपुरी एक्सटेंशन में प्लॉट नंबर 18 से 25 को अवैध रूप से एक ही प्लॉट में बदल दिया गया है;	(क) से (ड) :- मांगी गई जानकारी DUSIB से संबंधित हैं।
ख	क्या यह भी सत्य है कि इन प्लॉटों पर एक शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है;	
ग	क्या यह सत्य है कि डीयूएसआईबी ने इन प्लॉटों का एक सर्वे किया था जिसमें इनके मूल आवंटी नहीं पाए गए थे;	
घ	इन अवैध गतिविधियों के विरुद्ध इसे गिराने सहित अन्य कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण हैं;	
ड	सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है; और	
च	इन अवैध गतिविधियों को होने देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ने करने के क्या कारण हैं?	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र के भवन विभाग में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार सम्पत्ति पर अवैध निर्माण के विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट-1957 की धारा 343/344/345-ए के तहत कार्यवाही की गई है एवं दिनांक 11/11/2020 को तोड़फोड़ एवं सीलिंग की कार्यवाही भी की गई है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत है।

भवदीय

सदर अध्यक्ष आयुक्त
सदन एवं समिति, द0दि0न0नि0

52

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT. OF NCT OF DELHI,
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (JJR)

SURVEY REPORT

No.DD(JJR)/DUSIB/D:-123/2020

Dated:- 21/08/2020

Subject:- Site inspection report of plot No. 18 to 23, Block.13. Dakshinpuri Exten, N.D.

Director (T.P.) DUSIB is requested to conduct the complete survey of the above mentioned Plot showing the factual position regarding occupation & Un-authorized construction raised if any as well as amalgamation with adjacent plot.

Director (T.P.)

Dy. Director (JJR)

D.D. (Survey)

Pl. Putup report:-

21/8/20

Sh. Virender Singh
Surveyor

महोदय :- निर्देशानुसार विषय से संबंधित प्लॉट नं. 13 से 23 ब्लॉक नं. 13 दक्षिण पुरी स्कमैटिंग नई दिल्ली का सर्वेक्षण दल द्वारा स्थल सर्वेक्षण किया गया जिसकी विस्तृत रिपोर्ट इस प्रकार है :-
1. प्लॉट नं. 13/18 से 13/23 तक सभी प्लॉटों को मिलाकर बैसमेंट (Basement) व मूलतल (GROUND FLOOR) बनाया हुआ है और इससे ऊपर प्रथम तल पर प्लॉट नं. 13/24 और 13/25 को और मिलाकर प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल बनाया हुआ है।

P.T.O.

R-83/DY.DIR(SURVEY)/D:-123/2020
25/08/20

और चौथे तल पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका लाइफ प्लान बनाकर साथ संलग्न कर दिया गया है और दक्षिण मुहाने व मदनगरी के बड़े कोलोनी के ले आकर प्लान में विषय से संबंधित सभी प्लॉट को लाल पेन द्वारा दर्शा दिया गया है व ले आकर प्लान साथ संलग्न है।

2. मीन पर पुछाछ के दौरान कब्जा धारी का नाम भी पता चल चुका 5% भी सहज चला बताया गया।
3. इस सर्वे में हाईप डिजाइनिंग के अनुसार प्लॉट का साइज $6.86M \times 3.05M = 25$ वर्ग गज है, व 1.3 मंजिल निर्मित करना प्रस्तावित है।
4. कब्जा धारी द्वारा बैसमेंट में फर्नीचर को दुकान चल रहे मूलतः (GROUND FLOOR) पर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित दुकान चल रहे हैं।
- प्रथम तल (FIRST FLOOR) पर फर्नीचर व द्वितीय तल पर फर्नीचर संबंधित कार्य है, व तृतीय तल पर भी संबंधित कार्य चल रहा था व चौथी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था।

रिपोर्ट आगे कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

Sundar
31/08/20

उप निदेशक (सर्वेक्षण)

आ. (ए)

[Signature]
31/08/2020

DD (JSP) on card duty

ADCS/2 R
11/9/2020

1872/2020
R-896/20 (1532)
31/08/20

NO. D/3

M.(E)/97

Dated:- 15th September, 1997

C I R C U L A R

The Delhi Administration vide notification No. F. 2/22/E7-P/L&B/8949-66, dated 27th May, 1988 ordered to transfer the 44 resettlement colonies on lock, stock and barrel from D.D.A. to the Municipal Corporation of Delhi w.e.f. 1.6.1988. The maintenance of these colonies became the responsibility of the M.C.D. There has, however, been some confusion about the jurisdiction of authorities responsible for exercising building control activities in these resettlement colonies and also about the protection of open lands and maintenance of the markets/ shopping complexes located in these colonies. The markets consist of convenient shopping centres, Local shopping Centres, Community Centres, Special Component Stalls, Kiosks.

2, A meeting was held in the chamber of Commissioner, MCD on 23.8.1996, the minutes of which were circulated vide No. PM/1820/154/S/96/DD(P&M)/D-504, dated 30.8.1996. It was decided in the meeting that all the open spaces in the J.J. resettlement colonies which were taken over by the M.C.D. from the D.D.A. would be protected by the General Wing of the M.C.D. at every cost and under all circumstances. No encroachments on open public lands should be tolerated and wherever the same have taken place, corrective measures should be taken immediately for lodging FIRs. In addition to demolition action. As regards enforcement of building control activities in such colonies, it was decided that the building activities in all the J.J. and resettlement colonies would be controlled by the Building Deptt. of the M.C.D. It was also further decided that in all such colonies where people have carried out unauthorised constructions on more than one plots by amalgamating them, necessary action should be initiated under provisions of law. A circular was also issued vide No. D/423/Addl. Cm.(E)/96, dated 16.9.1996 under signatures of Shri V.K. Duggal, Commissioner, MCD whereby clear directions were issued that henceforth the General Wing of the M.C.D. would control the building activities in the said colonies. Copies of standard plans for the construction on the plots measuring 25 sq yds. in such colonies were also enclosed with the circular directing to take prompt action under relevant sections of the DMC Act

against the unauthorised constructions carried out in violation of these drawings/plans.

3. In the meeting held in the chamber of Commissioner on 8.9.1997 the issue regarding maintenance of markets located in these colonies came up for discussion and it was noted that some of the officers of the General Wing were not paying due attention to the maintenance of these markets on the plea that since the ownership of these markets vested with the Slum Department, it was their responsibility to maintain the markets. After detailed discussion it has been decided by the Commissioner that it is the responsibility of the General Wing of the M.C.D. to provide cleanliness, scavenging etc. in these markets.

4. The above instructions may please be noted for strict compliance by all concerned and they should immediately start regularly undertaking maintenance of the shopping complexes in all the resettlement colonies. There should now be no confusion about the jurisdictional responsibility regarding the land protection, prevention of unauthorised constructions and proper maintenance of the entire area of the J.J. resettlement colonies including markets.

5. This issues under order of the Commissioner.

Sd/-
(V.S. SHARMA)
ADDITIONAL COMMISSIONER (ENGG.)

DISTRIBUTION:-

1. All Addl. Cms./ Dy. Cm(HQs).
2. Engineer-in-Chief.
3. All Chief Engineers.
4. All Dy. Mpl. Commissioners.
5. Director/CSE.

Copy to:- Commissioner, M.C.D. for information.

NO.F.12/22/87-P/18B

Dated the 27th May, 1988.

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by sub-section(1) of section 12 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with notification of the Govt. of India, M/o Health, Family Planning and Urban Development No.10011, 28/67-UD dated.14.2.69, the Administrator of Union Territory of Delhi hereby denotify 44 resettlement colonies mentioned in the list enclosed (declared as developed areas) vide notification issued from time to time.

The Administrator of the Union Territory of Delhi is also pleased to order that the 44 resettlement colonies (list enclosed) will stand transferred lock, stock and barrel from Delhi Development Authority to the Municipal Corporation of Delhi w.e.f. 1.6.1988. The Municipal Corporation of Delhi will take over all the maintenance staff working in these colonies from the DDA excluding the Engineers; according to the M.C.D. pattern. Only those Engineers will revert back to the M.C.D. who were transferred to the DDA when these colonies were handed over to the DDA from M.C.D.

By Order.

Sd/-

(GNAGA DAS)

Commr. & Secretary (L&B)

No.F.12/22/87-P/L&B/0949-66

Dated the 27th May, 1988.

Copy forwarded to:-

1. Secretary to the Govt. of India, M/O, Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
3. Commissioner (Lands) DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
4. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
5. Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. Town Planner, M.C.D. Old Hindu College Building, K.Gate, Delhi.
7. Secretary DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
8. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
9. Secretary (Law & Judl.), Delhi Administration, Delhi.
10. Administrator, NDMC, Palika Bhawan, New Delhi.
11. Under Secretary (LSG), Vikas Bhawan, New Delhi.
12. Asstt. Housing Commissioner (Coordn.) Land & Building, Deptt. Delhi Admn, Vikas Bhawan, New Delhi.
13. Chief Engineer, DDA Vikas Sadan, INA, New Delhi.
14. Tehsildar (L&B) Vikas Bhawan, New Delhi.
15. Deputy Commissioner (Water), Link House, Bahadur Shah Zafar Marg, T.P. Estate, New Delhi.
16. Under Secretary (LA), Land & Building Deptt. Delhi Admn, Vikas Bhawan, New Delhi.
17. P.S. to Chief Secretary, Delhi Admn., Delhi.
18. P.S. to Commr. & Secretary (L&B), Delhi Admn., Delhi.

Sd/-

(GNAGA DAS)

COMM. & SECRETARY (L&B)

Contd...P/2.

1. ✓ Khayala Ph-I
2. ✓ Chauhhandi
3. ✓ Pandav Nagar
4. ✓ Shakurpur Ph-I
5. ✓ Shakurpur Ph-II
6. ✓ Khayala Ph-II
7. ✓ Khayala Ph-III
8. ✓ Maryana
9. ✓ Manglapuri
10. ✓ Madipur
11. ✓ Khanpur
12. ✓ Jwalapuri Ph-I
13. ✓ Jawala puri Ph-II
14. ✓ Hand Nagri Block A to E
15. ✓ Hand Nagri Blk F to L
16. ✓ New Seemapuri
17. ✓ Mochi Bagh
18. ✓ Wazirpur
19. ✓ Old Seemapuri
20. ✓ Seelampur Ph-I
21. ✓ Seelampur Ph-II
22. ✓ Trilokpur Ph-I & II
23. ✓ Seelampur Ph-II
24. ✓ Khichripur
25. ✓ Katyanpuri
26. ✓ Manmatpuri
27. ✓ Seelampur Ph-IV
28. ✓ Mangloi Ph-I
29. ✓ Mangloi Ph-II
30. ✓ Mangloi Ph-III
31. ✓ Mangolpuri
32. ✓ Sultanpuri
33. ✓ Jangpuri
34. ✓ Pankha Rd. & Ring Rd
35. ✓ Pankha Nagar
36. ✓ Dakshinapuri
37. ✓ Dakshinapuri Extn.
38. ✓ Tigr
39. ✓ Madangir Ph-II
40. ✓ Madangir Ph-I
41. ✓ Sunlight colony
42. ✓ Srinivaspuri
43. ✓ Gokulpuri
44. ✓ Haidarpur

(No more a resettlement colony).

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI
(PLANNING DEPARTMENT)

NO: D/3200 E E (P) II

DATED: 1-7-88

Copy to:-

1. E-I-C, for kind information.
2. All Chief Engineers
3. All D.Cs
4. All S.Es
5. All E.Es
6. Director C.S.E.
7. T.P.
8. A.C. (L & B)
9. A.C. (Community Services)
10. All Z.A.Cs/A.D.Cs (2 copies)

for information and necessary action.

This issues prior approval of Chief Engineer-II

Ex. Engineer (P) 11.7.88

Sd/-

V.C. G

11/12/88